कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) मदर डेयरी तथा दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिल्ली में दूध की सप्लाई के स्तर में कोई कमी नहीं की गई। अन्य महानगरों में दूध की सप्लाई में कमी आने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) इस समय सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) मदर डेयरी तथा दिल्ली दुग्ध योजना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान नामक पड़ौसी राज्यों के सहकारी डेयरी संघों से दूध प्राप्त करती हैं। इसके अलावा, मदर डेयरी गुजरात सहकारी संघ से भी दूध प्राप्त करती है। दिल्ली दुग्ध योजना इसके अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सहकारी समितियों और महाराष्ट्र सरकार की डेयरियों से भी दूध प्राप्त करती हैं।

(घ) चूंकि दूध की प्राप्ति की मौजूदा व्यवस्था संतोषजनक पाई गई है इसलिए सरकार ने ऐसे कोई प्रयास नहीं किए हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी द्वारा दूध की कीमतों में वृद्धि

2256. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष 1990 में तथा इस वर्ष की पहली छः माहों में दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी द्वारा कभी दूध के सीधे दाम बढ़ा कर और कभी दूध की गुणवत्ता में कमी करके दूध के दामों में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संस्थाओं में उस समय मूल्य वृद्धि द्वारा प्राप्त राशि का आंशिक लाभ दूध उत्पादकों को दिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि इस मूल्य वृद्धि से प्राप्त लाभ दूध उत्पादकों को नहीं दिया गया तो उसका क्या कारण था और क्या सरकार अब मूल्य वृद्धि के इस लाभ को दूध उत्पादकों को देने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) मदर डेयरी और दिल्ली दुग्ध योजना ने 14 दिसम्बर, 1990 से टोण्ड दूध में 50 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। दिल्ली दुग्ध योजना ने उसके बाद दूध के मूल्य में वृद्धि नहीं की है। मदर डेयरी ने 16 अप्रैल, 1991 से 5.50 रुपये प्रति लीटर की दर से डबल टोण्ड दूध की बिक्री आरम्भ कर दी।

(ख) और (ग) जी, हां। लाभ को दुग्ध उत्पादकों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारी डेयरी संघ से प्राप्त होने वाले दूध का मूल्य 63 पैसे प्रति कि.ग्रा. बढ़ा दिया गया था।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

Derailment of trains.

226. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI MIRA DAS:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of derailment of trains during the last three years;

(b) what are the remedial measures taken by Government in this regard;

(c) what action Government take against the persons responsible for the negligence in maintenance; and

(d) whether any incentives or disciplinary measures have been worked out for regular and very good performance of the staff and *vice-versa*?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) There were 457, 456 and 446 derailments during the years 1988-89, 1989-90 and 1990-91, respectively.

(b) Some of the important steps being taken to reduce derailments include strengthening/renewal of track structure, ultrasonic testing of rails, improving quality of out-turn from workshops, intensive and frequent inspections of installations in sensitive areas and patrolling of track in disturbed areas.

(c) Suitable disciplinary action is taken against the persons held responsible for negligence in maintenance of equipment.

(d) Railways have schemes of rewards and punishments to staff.

Compensation of passengers for late arrival/departure of trains

227. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI SOM PAL:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government propose to compensate the passengers for the delay in arrival and departure of trains beyond certain reasonable time; and

(b) whether incentives or disciplinary measures are worked out for regular and very good performance of the staff and *vice-versa*?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

Construction activities of Delhi Development Authority

228. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI RAM AWADHESH SINGH:
SHRI SOM PAL:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of registered applications pending with Delhi Development Authority for allotment of flats/shop/plots etc. as on date, categories-wise; and

(b) whether Government propose to take any urgent measures to hasten the tempo of house construction in Delhi; if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) As per Statement.

(b) DDA's plan is to construct 1,07,500 flats during the next four years ending 1994-95. To achieve this objective it is proposed to acquire more land in Urban extension area of Delhi for planned development and construction of houses. Further 700 hectares of residential land which will become available in Rohini Phase-III will accommodate about 23,000 more registrants in due course of time. There is also a proposal for acquisition of about 2500 hectares of land adjoining the present project to accommodate the balance registrants under Rohini Residential Scheme during the 8th Five Year Plan.

Statement

(a) *Residential flats*: The category-wise details of registrants pending for allocation/allotment of flats are given as under:—

Sl. No.	Category	No. of registrants awaiting allotment
1	MIG	22,567
2	LIG	26,962
3	Janta	7,919
4	SFS	18,646
	TOTAL :	76,094

(b) *Commercial flats*: A total of 562 registrants are awaiting for allotment of commercial flats.